

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
संकल्प

विषय:— वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान—सम्प्रति भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा के निर्माण योजना में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना से प्राप्त अनुरोध एवं प्राप्त विधिक राय के आलोक में Arbitration Award के विरुद्ध एकमुश्त रु० 1,50,00,00,000/— (रुपये एक अरब पचास करोड़) मात्र के प्रावधान सहित कुल रु० 7,46,64,00,000/—(रुपये सात अरब छियालीस करोड़ चौसठ लाख) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में भुगतान हेतु रु० 1,50,00,00,000/—(रुपये एक अरब पचास करोड़) मात्र राशि की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।

स्वास्थ्य विभाग के सकल्प संख्या-1/विविध-148/2009-255(1) दिनांक-25 03 2010 के द्वारा नालन्दा जिला में वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के माध्यम से कराने हेतु रु० 6,13,11,09,273/—(रुपये छ अरब तेरह करोड़ ग्यारह लाख नौ हजार दो सौ तेहत्तर) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी।

पुनः निगम के पत्राक-631, दिनांक-30 09 2016 द्वारा सम्पन्न कराये जा रहे कार्यों के पुनरीक्षण के उपरान्त रु० 5,96,64,00,000/— मात्र का पुनरीक्षित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया था, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या-85(1), दिनांक-30 01 2017 के द्वारा दी गयी। 2- ज्ञातव्य है कि उक्त योजना पूर्ण हो चुकी है एवं स्वीकृत राशि (रु० 596 64 करोड़) भी निर्माण एजेन्सी को आवंटित की जा चुकी है। इस योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इस कार्य के संवेदक के द्वारा Escalation मद के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना के अस्वीकृत दावे के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर किया गया, जिसमें अन्तिम निर्णय एवं विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त विधिक राय के आलोक में Out of Court Settlement कर Arbitration Award की राशि के विरुद्ध एकमुश्त 150 00 करोड़ रुपये का भुगतान संवेदक को करने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना के कार्यालय पत्राक- 2011, दिनांक-15 07 2025 के द्वारा संवेदक से प्राप्त Undertaking समर्पित किया गया है कि एकमुश्त रु० 150 00 करोड़ के अतिरिक्त अन्य कोई दावा नहीं किया जायेगा। साथ ही प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि Arbitration & Conciliation Act 1996 की धारा 34 के तहत दायर अपील को उक्त राशि के स्वीकृति के पश्चात् वापस कर लिया जायेगा।

3- उक्त परिप्रेक्ष्य में मन्त्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरान्त वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान—सम्प्रति भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा के निर्माण योजना में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना से प्राप्त अनुरोध एवं प्राप्त विधिक राय के आलोक में Arbitration Award के विरुद्ध एकमुश्त 150 00 करोड़ रुपये के प्रावधान सहित कुल रु० 7,46,64,00,000/— (रुपये सात अरब छियालीस करोड़ चौसठ लाख) मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या-259(7), दिनांक-28 08 2025 द्वारा दी गयी है। इस संदर्भ में संवेदक को भुगतान किये जाने हेतु राशि की नितान्त आवश्यकता को देखते हुए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना के पत्राक-3043, दिनांक-24.09 2025 एवं 3051, दिनांक-25 09.2025 द्वारा राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

4- इस व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 050 भूमि-0103-नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड-20-4210030500103, विषय शीर्ष-53 01 मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबधित राशि से किया जाएगा। इस विपत्र कोड अधीन वर्तमान में राशि के उपबंध के कमी को देखते हुए Out of Court Settlement कर Arbitration Award की राशि के

विरुद्ध एकमुश्त 150.00 करोड रुपये का भुगतान बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करते हुए की जानी है। बी सी एफ की प्रविष्टि से पूर्व विभाग द्वारा योजना एवं विकास विभाग से उद्ब्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

5- उपरोक्त के आलोक में वर्द्धमान आयुर्विज्ञान सस्थान-सम्प्रति भगवान महावीर आयुर्विज्ञान सस्थान, पावापुरी, नालदा के निर्माण योजना में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना से प्राप्त अनुरोध एवं प्राप्त विधिक राय के आलोक में Arbitration Award के विरुद्ध एकमुश्त रू० 1,50,00,00,000/- (रुपये एक अरब पचास करोड) मात्र के प्रावधान सहित कुल रू० 7,46,64,00,000/- (रुपये सात अरब छियालीस करोड चौसठ लाख) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में भुगतान हेतु रू० 1,50,00,00,000/- (रुपये एक अरब पचास करोड) मात्र राशि की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6- उक्त योजना एवं बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्, बिहार सरकार की बैठक दिनांक-03.10.2025 के मद सख्या-104 के रूप में सम्मिलित किया गया है।

7- संकल्प प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या-01/विविध-36/2024 के रूप पृ०-53-57 टि० में प्राप्त है।

8- यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शम्भु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापाक-01/विविध-36/2024 - 341 (7) /पटना, दिनांक- 04/10/2025
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन एवं सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य मंत्री सचिवालय विभाग/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विकास आयुक्त के आप्त सचिव/मन्त्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिलाधिकारी, नालदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7A, स्वास्थ्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।